

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश की मात्रा पर निर्णय करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को स्वीकृति दी

Posted On: 18 JAN 2017 4:52PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) में विनिवेश की मात्रा पर निर्णय करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को स्वीकृति दी। यह विनिवेश विषयानुसार के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि उपक्रमों 51 फीसदी सरकार की हिस्सेदारी बनी रहेगी। यह अगस्त 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से स्वीकृत वैकल्पिक तंत्र के परिचालन के अतिरिक्त होगा।

इससे लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी और विनिवेश प्रक्रिया में तेजी आएगी।

AKT/VBA/SH/VS

(Release ID: 1481042) Visitor Counter: 16

f







in